No: Shiksha-Shimla(G-1) Estimate-
O/O the Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

Dated: Shimla-171001

Director of Higher Education
150243-150313
14 DEC 2018
Shimla-1

To

All the Principal/Headmaster,
GSSSs/GHSs Chopal Constituency Distt. Shimla.

Sub:- Report on news cuttings regarding scam of Rs. 4.00 crore in r/o construction of school building.

Memo,

With reference to Directorate of Higher Education Himachal Pradesh office letter No. EDN-H(9)3-7/2009-10 (A.A.&E.S.) dated 03.11.2018 vide which photocopy of news cutting published in News paper "Divya Himachal" dated 26.10.2018 from Private Secretary to the Secretary (Education) to the Govt. of HP has been received in this office on the above cited subject. (Copy enclosed).

In this regard, it is directed that name of such school in Chopal constituency alongwith detailed report may be sent to this office within 02 days if, above noted scam of amount is appeared so, that same could be sent to the higher authority for further necessary action.

O/c Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

Endst. No. Even dated: Shimla-171001
Copy forwarded to:-

1. The Director of Higher Education H.P. Shimla-01 for information please.

14/12/18

O/c Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

शिमला के प्रत्याशी पर कल चर्चा करेगी कांग्रेस

चुनावी रणनीति बनाने के लिए जुटेंगे पदाधिकारी, वर्तमान सांसद की खामियों पर होगा मंथन

■ विशेष संवाददाता, शिमला

शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदारों को लेकर गुरुवार को शिमला में मंथन किया जाएगा। शिमला से कई दावेदार हैं, जिनके नामों पर चर्चा होगी और अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपने-अपने नेताओं के नाम सुझाएंगे। वैसे इस चर्चा पर अंतिम मुहर आलाकमान ने ही लगानी है, परंतु फिर भी पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल सभी से उनका फीडबैक लेना चाहती हैं।

शिमला के बाद शेष तीन लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर इस तरह का मंथन किया जाएगा, जिसके बाद एक संयुक्त रिपोर्ट राहुल गांधी को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में कांग्रेस प्रभारी संभावित नामों का जिक्र करने के साथ उनके गुण व दोष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगी। शिमला में होने जा रही इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए व्यापक रणनीति बनेगी।

उनसे उम्मीदवारों के नामों के अलावा शक्ति कार्यक्रम का फीडबैक भी लिया जाएगा। इसमें जाना जाएगा कि अभी तक कितने लोगों ने यहां पर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसके अलावा इस बैठक में जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा होगी जिसमें देखा जाएगा कि अभी तक कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिली है। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भी मंथन होगा ताकि उन बातों को कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में शामिल कर सके। इसके साथ यहां पर बूथ कमेटियों के गठन व कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर भी विचार होगा। भाजपा के मौजूदा सांसद द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र में अब तक वादों के अनुरूप नहीं किए गए कार्यों पर भी यहां चर्चा होगी, जिन्हें कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा दूसरे कद्दावर नेता भी उपस्थित रहेंगे जिनसे चर्चा की जाएगी।

यहां तीन दिन रहेंगी प्रभारी रजनी पाटिल

रजनी पाटिल यहां पर तीन दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पद से सुखविंदर सुक्खू को हटवाने की विरोधी खेमे की कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हुई हैं। तीन दिन के लिए रजनी पाटिल का यह दौरा इसी बात का द्योतक है। उनके आने पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अभी राहुल गांधी ने दूसरे राज्यों में भी अध्यक्षों को नहीं हटाया है, लिहाजा हिमाचल में भी ऐसा नहीं किया गया है।

स्कूल भवन निर्माण में चार करोड़ का घोटाला

वर्ष 2004 में बजट मिलने के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम, कौन डकार गया र[illegible]

■ सिटी रिपोर्टर, शिमला

- 15 साल में एक ईंट नहीं लगा पाया विभाग
- राज्य सरकार ने दिए विभाग को फिर जांच के आदेश
- [illegible] शामिल होंगे [illegible] शिक्षा अधिकारी

हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार यह सवाल किसी शिक्षक नहीं, बल्कि ऑफिस में बैठने वाले बाबुओं पर उठे हैं। हैरानी की बात है कि वर्ष 2004 के बाद स्कूलों के नए भवन के लिए बजट मिलने के बावजूद एक ईंट भी भवन निर्माण के लिए नहीं लग पाई है।

हैरानी की बात है कि करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार पंद्रह सालों में जिलों व हर ब्लॉक को दे चुकी है। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि इतने सालों से जो बजट राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत किया गया, वह स्कूल निर्माण पर खर्च ही नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने स्कूल निर्माण के नाम पर प्रदेश सालों से अभी तक चार करोड़ के घोटाले की आशंका जताई है। इतने बड़े घोटाले के बाद सरकार भी हैरान है कि आखिर इतना सारा बजट कैसे खर्च नहीं किया गया व इसकी जानकारी अभी तक विभाग में भी क्यों उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए अभी तक कितना बजट जिला और ब्लॉक अफसरों को दिया गया, इसकी रिपोर्ट मंगवा ली गई है। शिक्षा विभाग को पंद्रह सालों की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में विभाग को बताना होगा कि स्कूल निर्माण का पैसा किस ऑफिस अफसर के पास जाकर आगे नहीं [illegible] जिला उपनिदेशक, ब्लॉक ऑफिस रिपोर्ट इस दौरान तैयार करवाई [illegible] दौरान शिक्षा विभाग के कई अधिक[illegible] घेरे में आ सकते हैं।

ऐसे हुआ खुलासा

[illegible] के दौरान [illegible] अफसरों [illegible] सामने आया कि स्कूल के लिए तो वर्ष 2004 में ही बजट दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद काम शुरू नहीं हो पाया। इसी के बाद सरकार हरकत में आई।

शिक्षा सचिव [illegible]

[illegible]

शिक्षा सचिव ने वापस भेजा केस

उपलब्ध करवाई जानकारी, गृह विभाग देखेगा आगे की प्रक्रिया

■ विशेष संवाददाता, शिमला

छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने कमेंट्स के साथ मामला गृह विभाग को वापस भेज दिया है। बताया जाता है कि सीबीआई ने गृह विभाग की मार्फत कुछ जानकारियां मांगी थी, जो शिक्षा विभाग के सचिव ने उपलब्ध करवा दी हैं।

शिक्षा सचिव से मामला वापस गृह विभाग को गया है, जिसके बाद विस्तृत जानकारी सीबीआई को जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पुलिस द्वारा उन्हें मामला [illegible] कि आखिर सीबीआई को इसे क्यों सौंपा गया है। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग ने इस पर जवाब दिया है कि छात्रवृत्ति घोटाला न केवल प्रदेश से जुड़ा है, बल्कि इसमें दूसरे राज्यों की एजेंसियां भी शामिल हैं। बाहरी राज्यों की संस्थाओं के इसमें शामिल होने के चलते राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच करवाकर [illegible] सीबीआई को यह मामला सौंपा गया है। इस जवाब के साथ शिक्षा सचिव की ओर से गृह विभाग को मामला भेज दिया गया है। सीबीआई को जांच देने से पहले सरकार ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी, जिस पर एक परफॉर्मा सीबीआई की तरफ से राज्य को भेजा गया।

शिक्षा विभाग ने इसमें जरूरी जानकारी देकर इसे वापस कर दिया है। इसमें [illegible] का भी एक मामला है, जिसे लेकर अभी फैसला लिया जाना है। छात्रवृत्ति घोटाला 215 करोड़ रुपए का बताया जाता है।

250 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला